सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट की

मुख्य

विशेषताएं

2022-2023

फरवरी, 2022

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

प्रमुख विशेषताएं

अमृत काल के लक्ष्य

1 विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केन्द्रण

2 प्रद्योगिकी जनित विकास, उर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन

3 निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहु तायतसार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सदचक्र

चार प्राथमिकताएं

- पीएम गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता संवर्ध्न और निवेश, उदीयमान अवसर, उर्जा संक्रांति और जलवायुपरक कार्य
- निवेश का वित्तपोषण

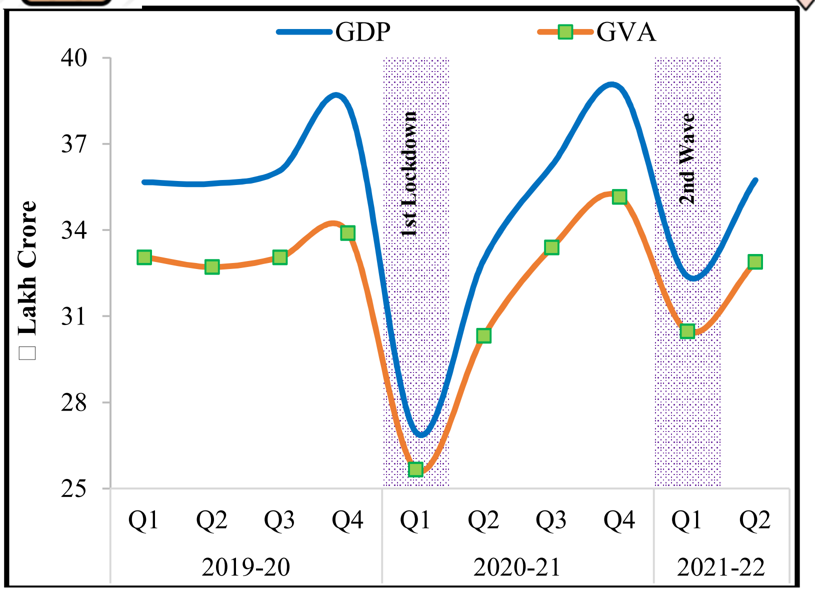

अर्थव्यवस्था की बहाली, देश की प्रतिरोधक क्षमता की द्योतक

भारतीय अर्थव्यवस्था - सतत बहाली का प्रदर्शन

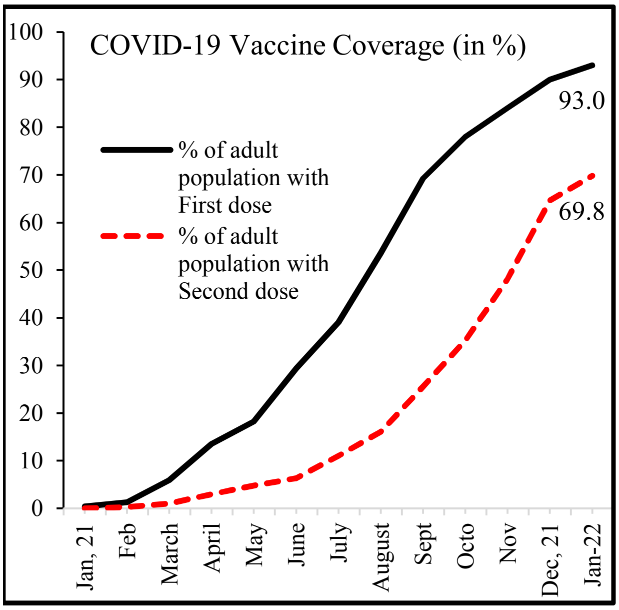

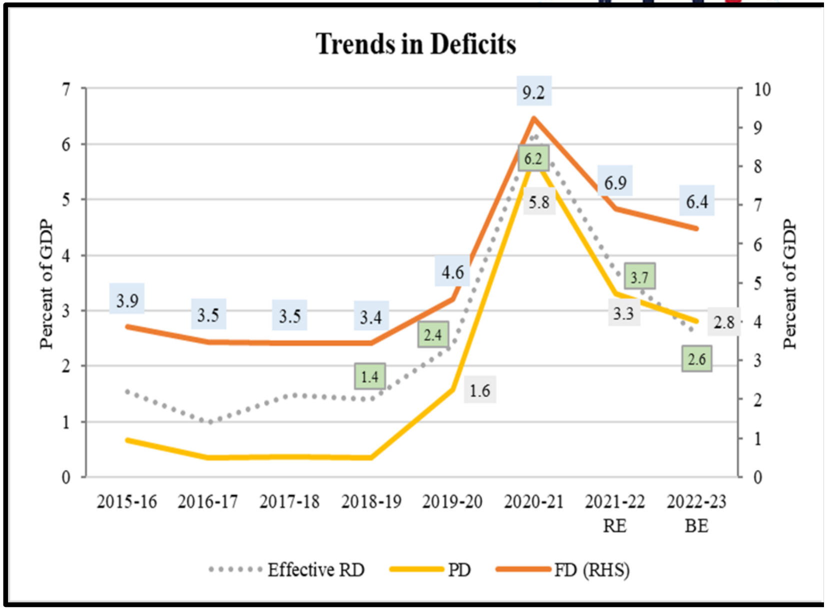

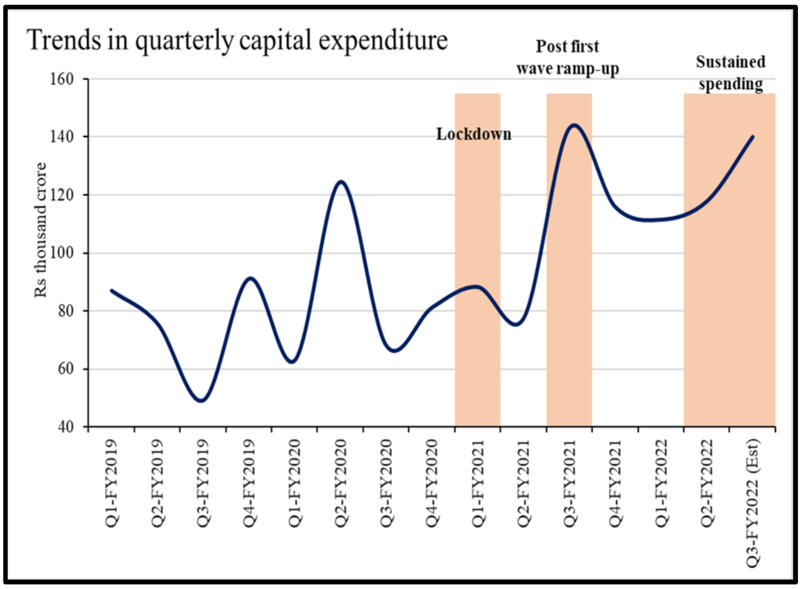

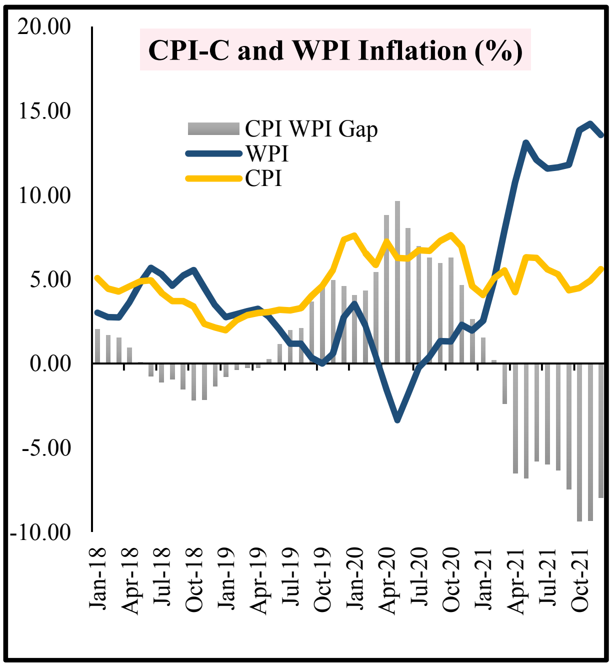

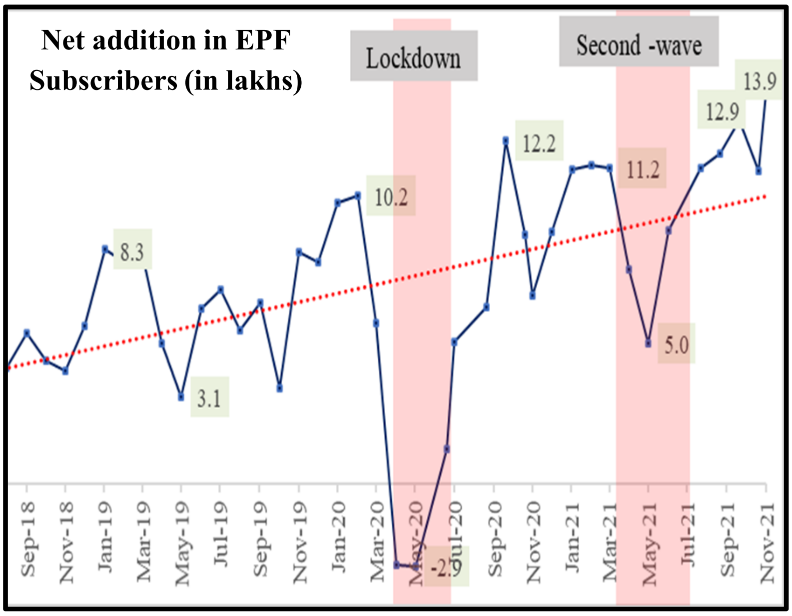

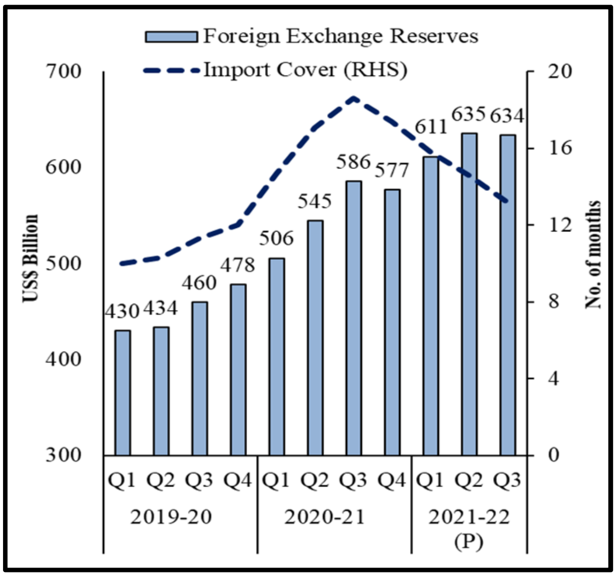

पीएम गतिशक्ति

- सात इंजनों यथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोटर्स, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लोजिस्टिक अवसंरचना से संचालित
- राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसका उददेश्य विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लोजिस्टिक सहक्रिया है

एक्सप्रैस वेस के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, 2022-23 में 25000 किलोमीटर राष्टीय राजमार्गों का काम पूरा करना

- यूनीफाईड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म जिससे सभी मोड आपरेटरों में डाटा विनिमय हो सके
- यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबाइलिटी स्टैक
- पीपीपी के तहत 4 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क के स्थापना, जिसके लिए 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे

- एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों के प्रेषण में सुविधा हो
- वन स्टेशन वन प्रोडक्ट
- कवच का क्षेत्र विस्तार
- नई जनरेशन की 400 बंदे भारत टेन्स

- सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमोडल संपर्क
- परंपरागत सड़कों के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में नेशनल रोपवेस डेवलेपमेंट प्लान
- अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

- गंगा नदी से सटे कृषक भूम से प्रारंभ होने वाले रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन
- कदन उत्पादों के फसलोंपरांत मूल्य संवर्धन, उपभोग और ब्रांडिग को प्रोत्साहन

- पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता
- किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग
- कृषि स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना

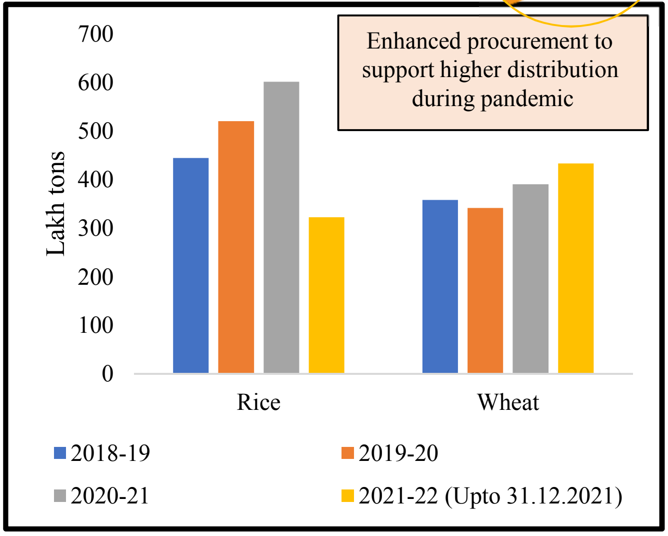

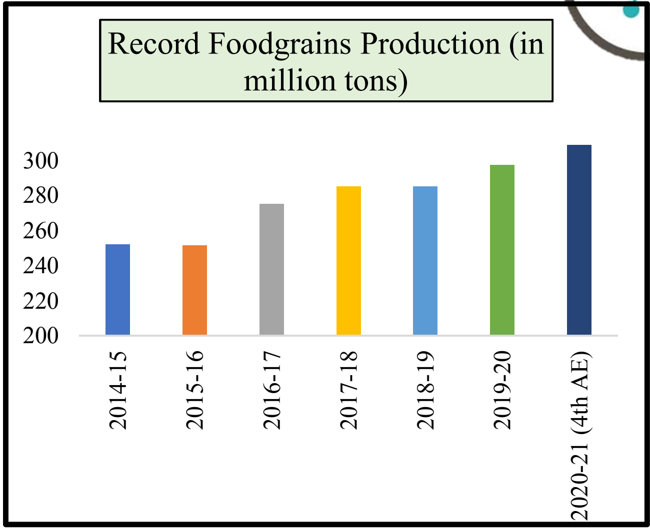

- केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन जिससे 9.1 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिल सकेगा।
- ऐसी ही 5 और परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

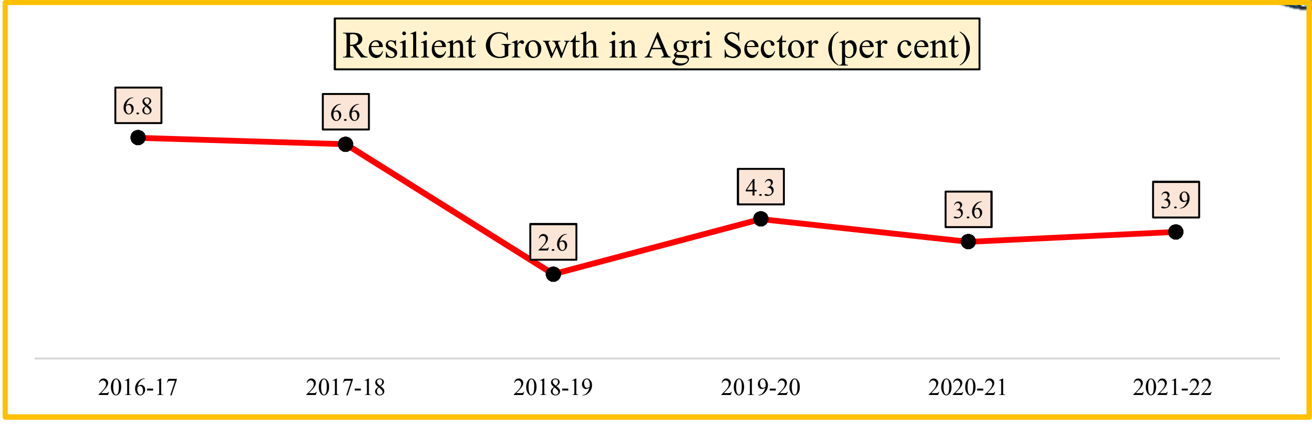

शिक्षा

गुणवत्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकरण

वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना

महत्वपूर्ण चिन्तन कौशल और उत्प्रेरिक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं और कौशलपरख ई-प्रयोगशालाएं

एक डिजीटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें विश्वस्तरीय गुणवत्ताप्रद सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी

डिजीटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ताप्रद ई-विषयवस्तु उपलब्ध कराई जाएगी

कौशल विकास

ऑनलाईन टेनिंग को बढावा देने के लिए कोशल एवं आजीविका हेतु डिजीटल ईको सिस्टम (DESH-Stack e-portal)

Drone-As-A-Service के लिए द्रोण शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअपस को बढ़ावा दिया जाएगा

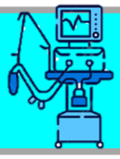

स्वास्थ्य

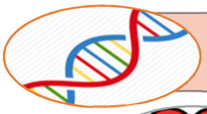

नेशनल डिजीटल हैल्थ ईकोसिस्टम को लागू किया जाएगा

गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेली मेन्टल हैल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा

एकीकृत कार्यक्रम – मिशन शक्ति, मिशन वात्स्लय, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा

दो लाख आंगनवाडियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में समुन्नयन

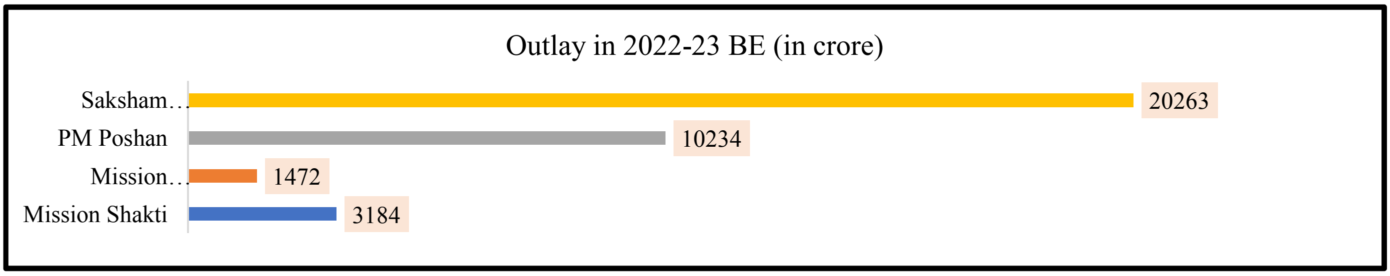

सभी समवेशी कल्याण पर ध्यान का केन्द्रण

1. हर घर नल से जल – इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा
2. पीएम आवास योजना – 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है
3. PM-DevINE: उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास के लिए धन
4. महत्वाकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम: महत्वाकांक्षी जिलों के पिछड़े हुए ब्लकों के विकास के लिए
5. वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम- विकास से वंचित पूर्वी सीमा के गांव के विकास का लक्ष्य
6. डाकघरों के द्वारा डिजीटल बैंकिंग- शत प्रतिशत डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था
7. डिजीटल पेमेंटस- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजीटल बैंकिंग यूनिटस की स्थापना

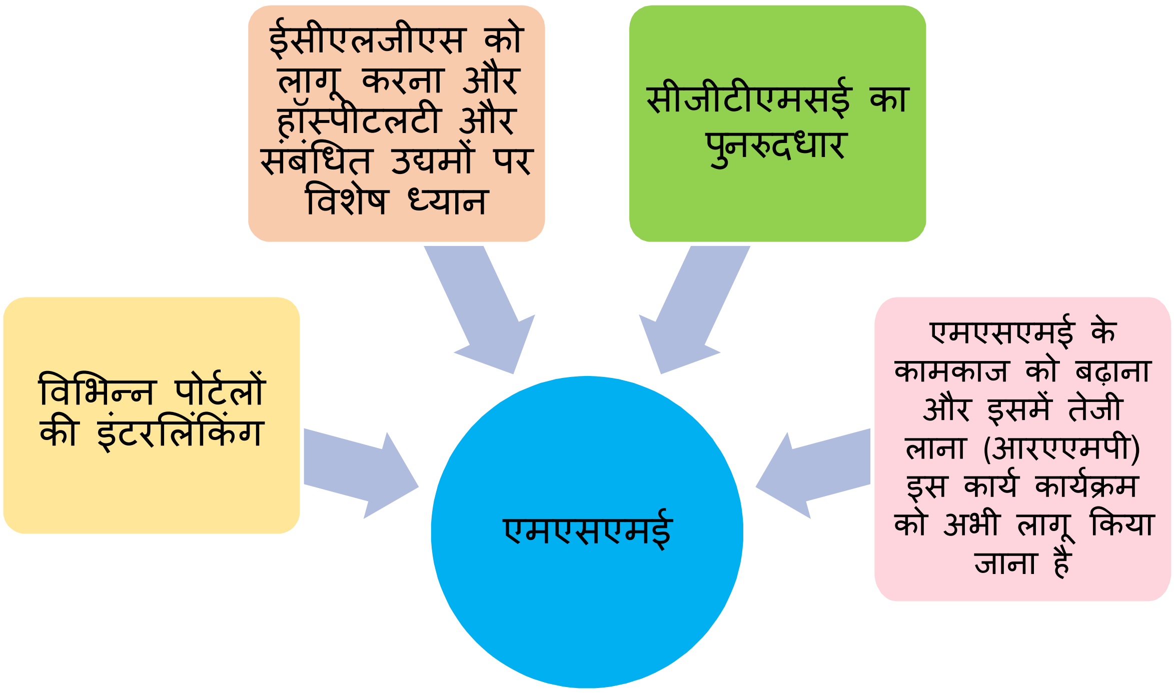

उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश

ईस ऑफ डूइंगि बिसिनेस 2.0

विश्वास आधारित शासन

आईटी सेतुओं के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का समेकन

PARIVESH Portal के क्षेत्र का विस्तार

भू-दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनीक लैंड पार्सल आईडेंटिटी िफकेशन नम्बर

कंपनियों के स्वैच्छिक समापन के लिए C-PACE की स्थापना

सरकारी अधिप्राप्ति में एन्ड टू एन्ड ऑन लाइन सिस्टम और सियोरिटी बॉन्ड का उपयोग

एवीसीजी प्रोत्साहन कार्यबल

पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 5जी को समर्थन

उद्योग, स्टार्टसअप और एकेडेमिया के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास का प्रारंभ

ईस ऑफ लिविंग

चिपयुक्त ई-पासपोर्ट को जारी किया जाना

भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन स्कीमों का क्रियान्वयन और संक्रमण उन्मुखी विकास

शहरी नियोजन के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना

शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू करना

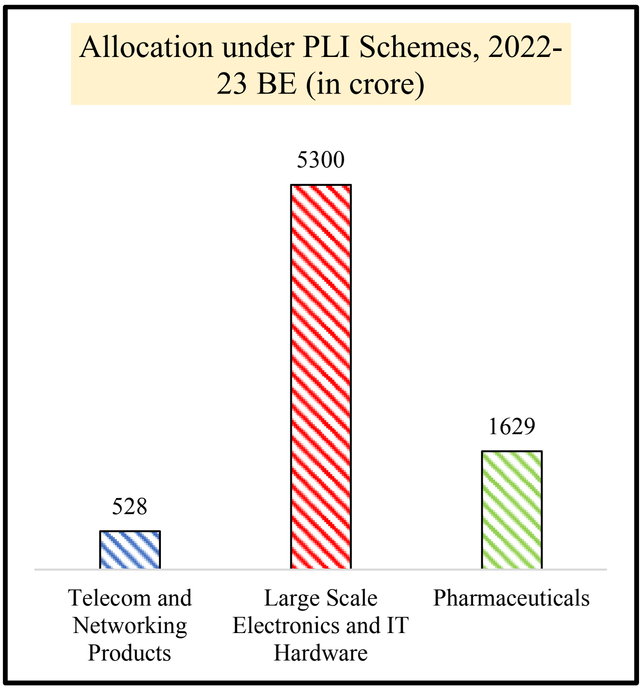

निवेश का वित्तपोषण

2022-23 में निजी निवेश और मांग को बनाये रखने के लिए सार्वजनिक निवेश

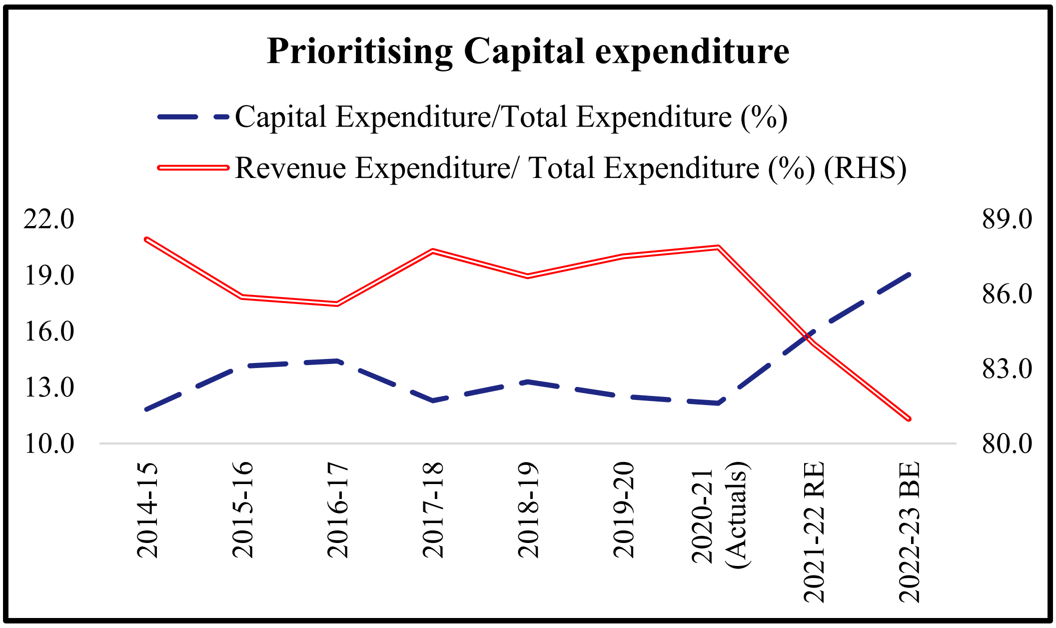

2022-23 से आरबीआई के द्वारा डिजीटल रुपये का संचलन

डाटा सेंटर्स और इनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए अवसंरचनात्मक स्थिति

उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश के द्वारा निवेश में सहायतापरक उपाय

हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु ग्रीन बॉंडस

संसाधनों को जुटाना

उदीयमान क्षेत्रों के लिए सम्मिश्रित वित्त

राज्यों को और अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान करना

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की स्कीम के लिए वर्धित परिव्यय

2022-23 में राज्यों के लिए जीएसडीपी के 4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी जिनमें से 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्रीय सुधार से संबंधित होगा

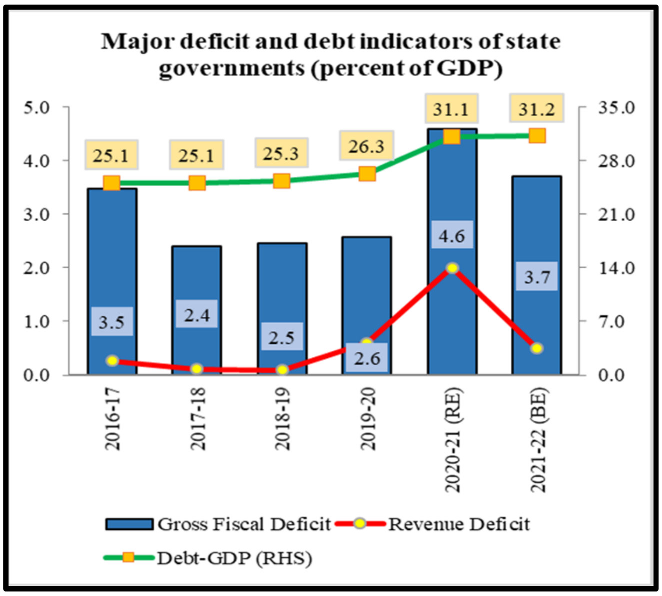

कर प्रस्ताव ₹

गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर कर सकने की अनुमति देना

- विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत देना
- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पि न्यूनतम कर दर और अधिभार में कमी करना

राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को बढ़ाना

कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टसअप को शामिल करने की अवधि का बढ़ाना

Buoyant GST collections during 2021-22 (Rs lakh crore)

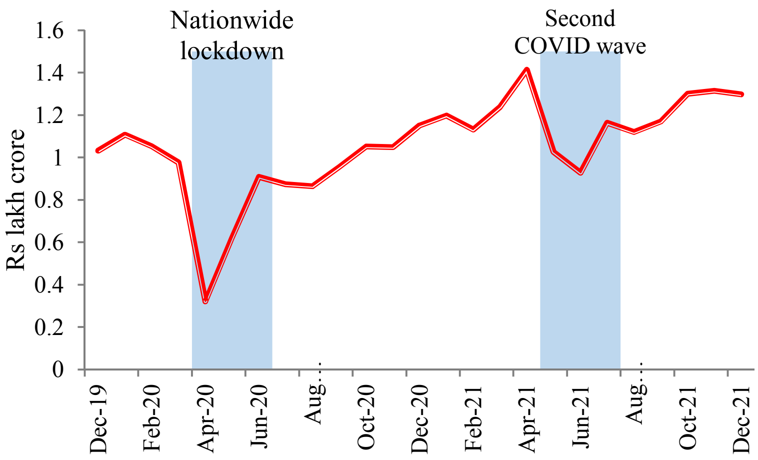

- अभासी परिसंपत्ति के अंतरण से हाने वाली आय पर 30 प्रतिशत का कर लगाना
- बार बार की अपीलों से निजात पाने के लिए मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंधन

आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को व्यापारिक व्यय न माना जाना

•विशेष आर्थिक जोनों में सीमा शुल्क प्रशासन को पूरी तरह आईटी संचालित किया जाएगा

•पूंजीगत माल और परियोजना आयातों में रियायती दरों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा और 7.5 प्रतिशत की आसान टेरिफ दर लागू की जाएगी

•सीमाशुल्क छूट की समीक्षा और टेरिफ का सरलीकरण

•घरेलू इलैक्टिनिक विनिमार्ण में सुविधा प्रदान करने हेतु ग्रडेड दर संरचना को लागू करने के लिए सीमीशुल्क की दरों में संशोधन किया जा रहा है

•भारत में विनिर्मित कृषि क्षेत्र के उपस्करों और औजारों पर दी जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाना

•स्टील के कबाड़ पर भी सीमाशुल्क से छूट को लागू करना

•इसक्रिंप एक्वाकल्चर के लिए जरूरी कतिपय इनपुटस पर शुल्क में कटौती

•अनब्लैंडिड ईंधन पर अतिरिक्त विचलन उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा

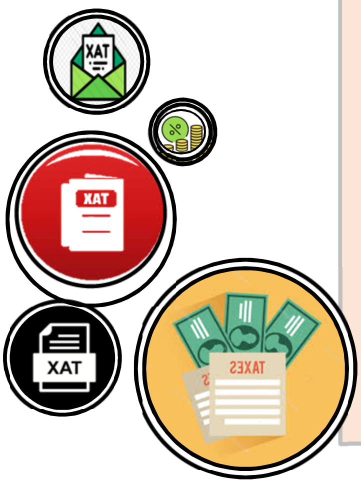

..... से रुपये का आगमन

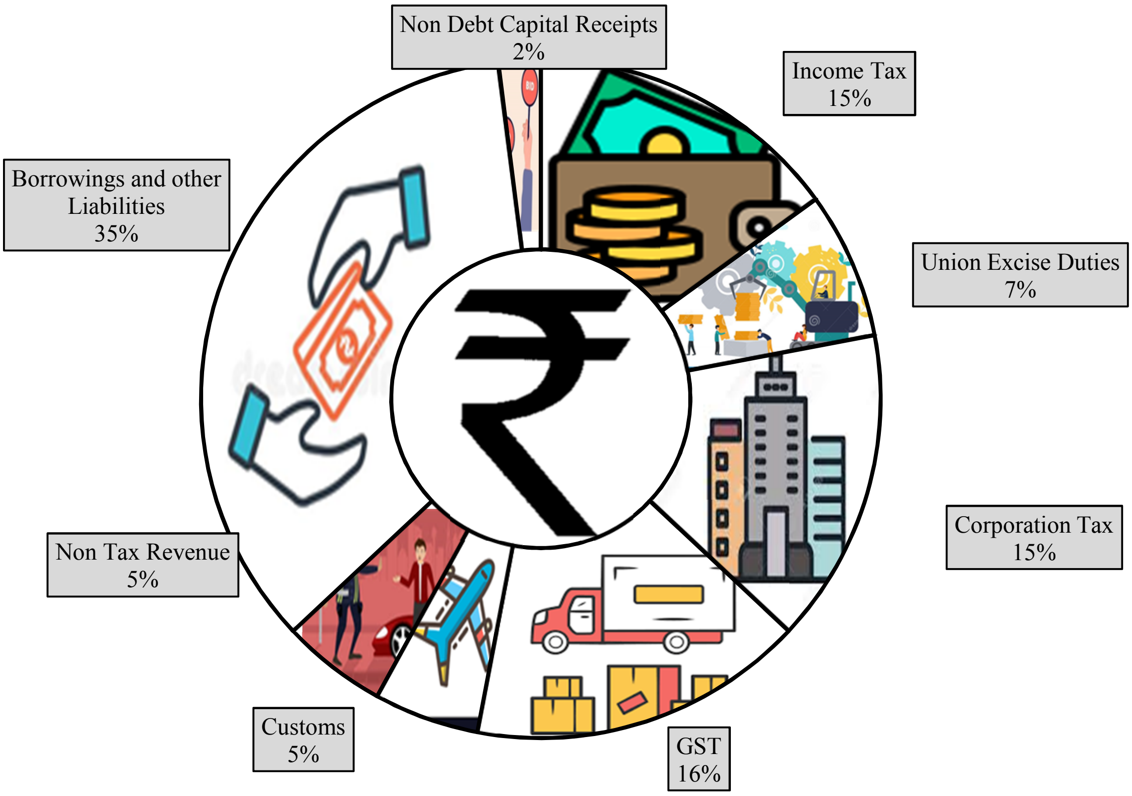

..... को रुपये का आगमन

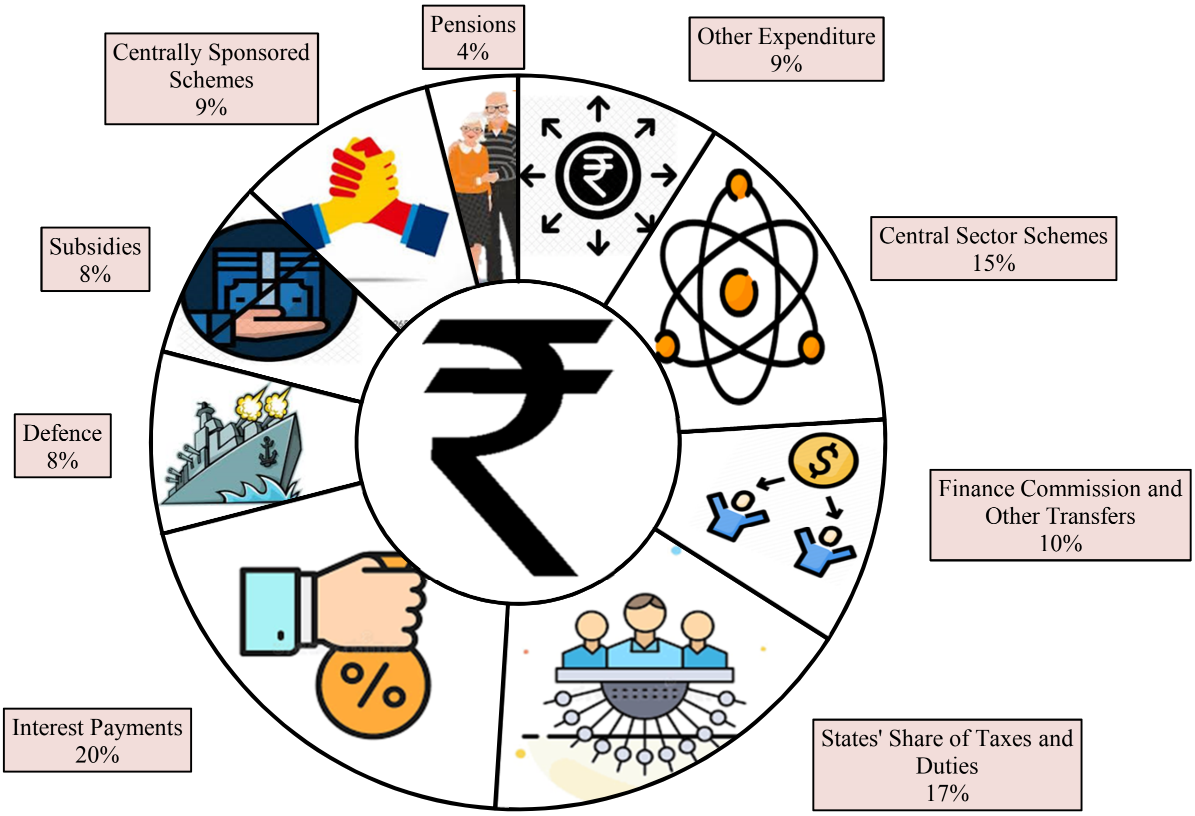

बजट एक नजर में

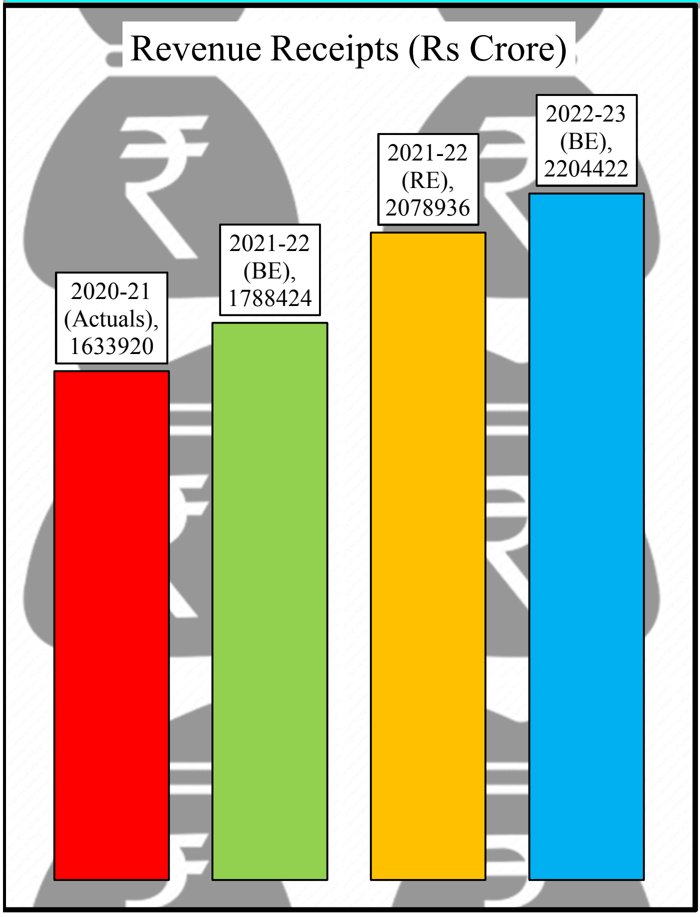

Revenue Receipts (Rs Crore)
2020-21 (Actuals), 1633920
2021-22 (BE), 1788424
2021-22 (RE), 2078936
2022-23 (BE), 2204422

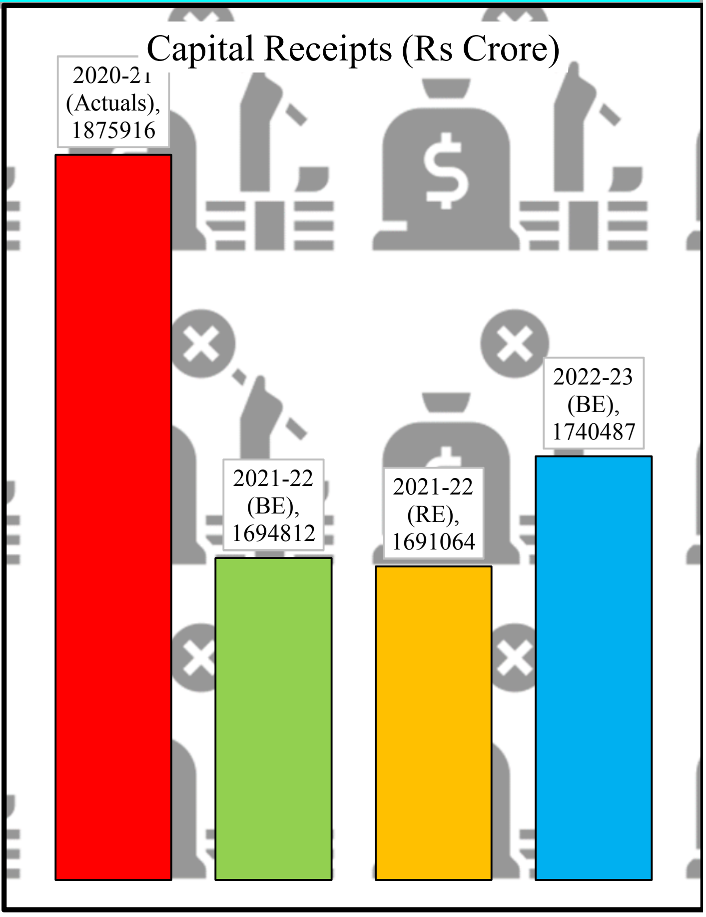

Capital Receipts (Rs Crore)
2020-21 (Actuals), 1875916
2021-22 (BE), 1694812
2021-22 (RE), 1691064
2022-23 (BE), 1740487

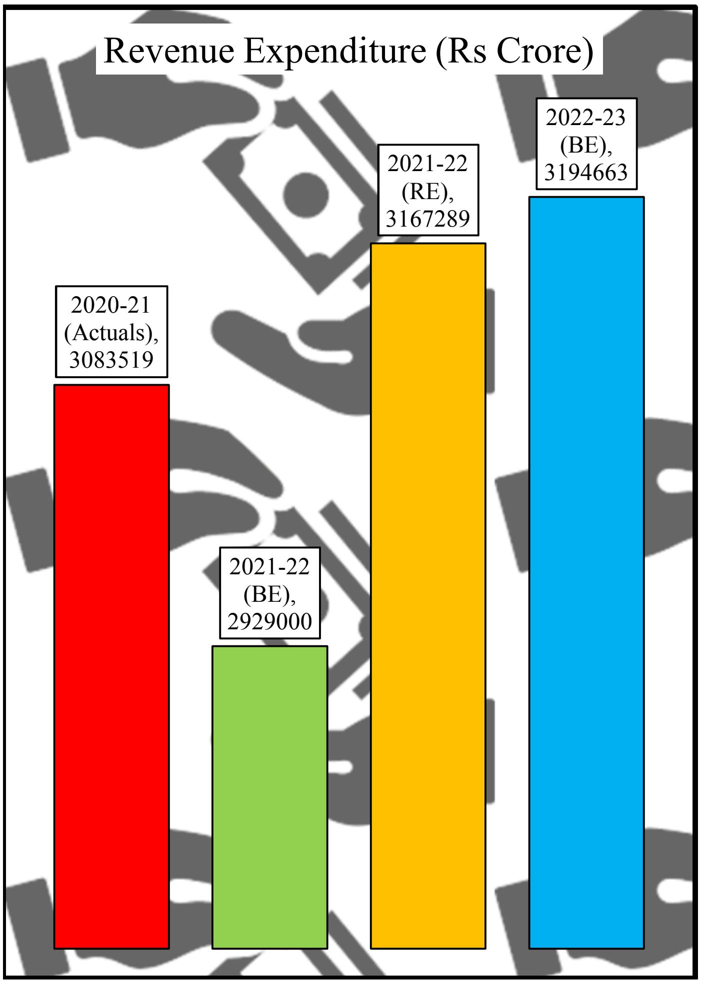

Revenue Expenditure (Rs Crore)
2020-21 (Actuals), 3083519
2021-22 (BE), 2929000
2021-22 (RE), 3167289
2022-23 (BE), 3194663

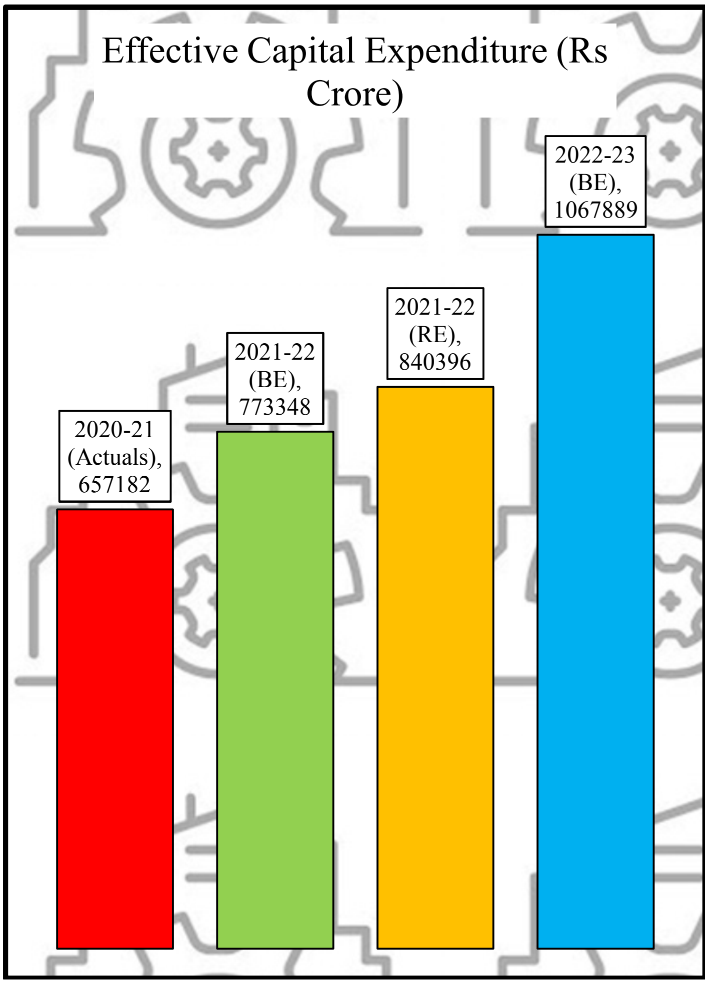

Effective Capital Expenditure (Rs Crore)
2020-21 (Actuals), 657182
2021-22 (BE), 773348
2021-22 (RE), 840396
2022-23 (BE), 1067889

प्रमुख योजनाओं के लिए आबंटन

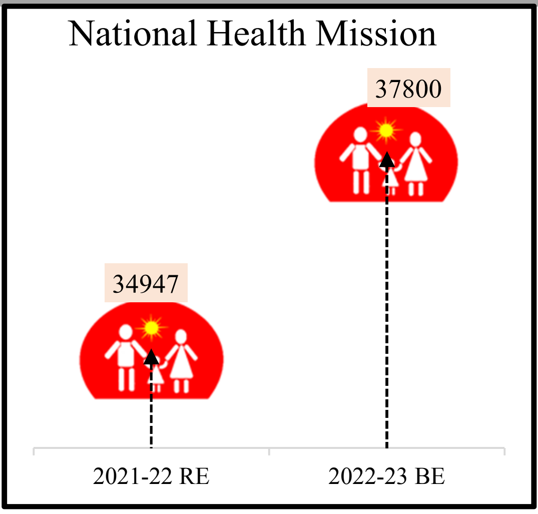

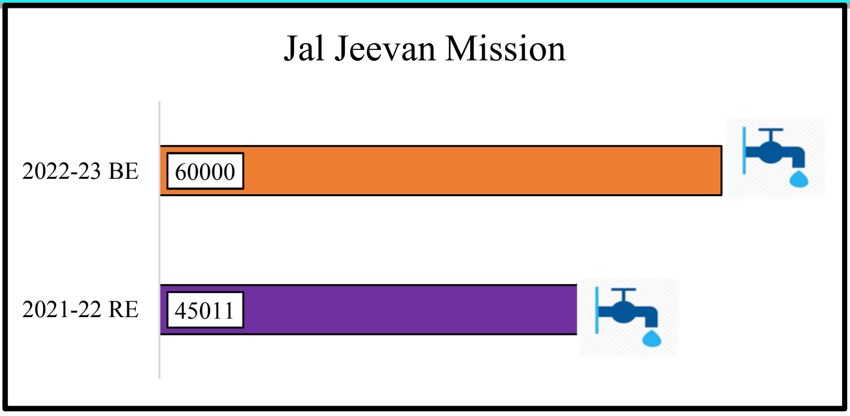

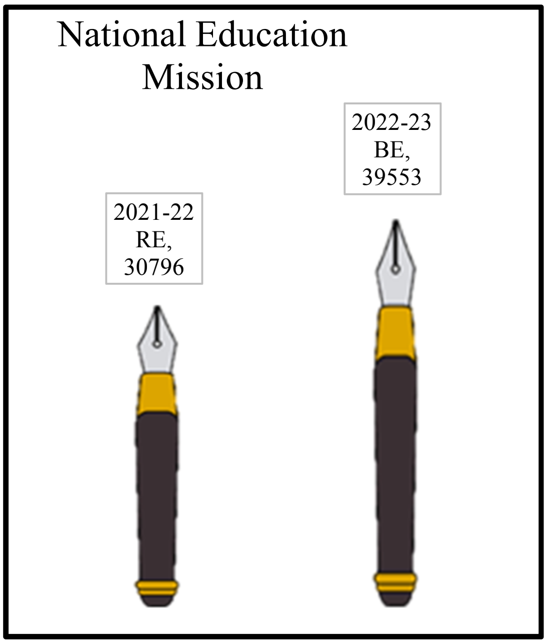

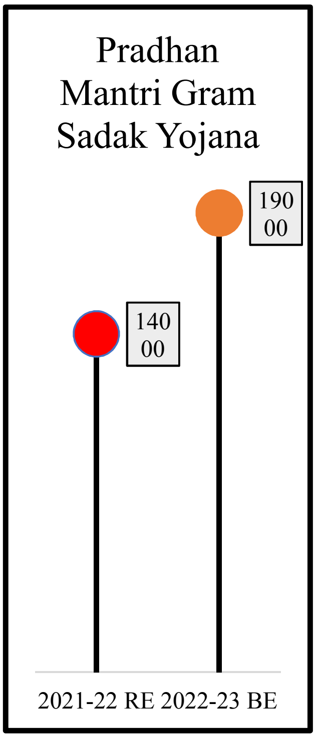

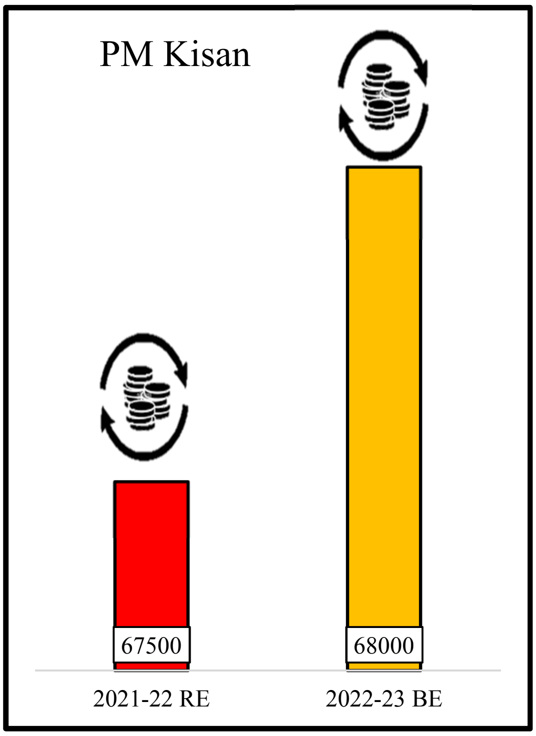

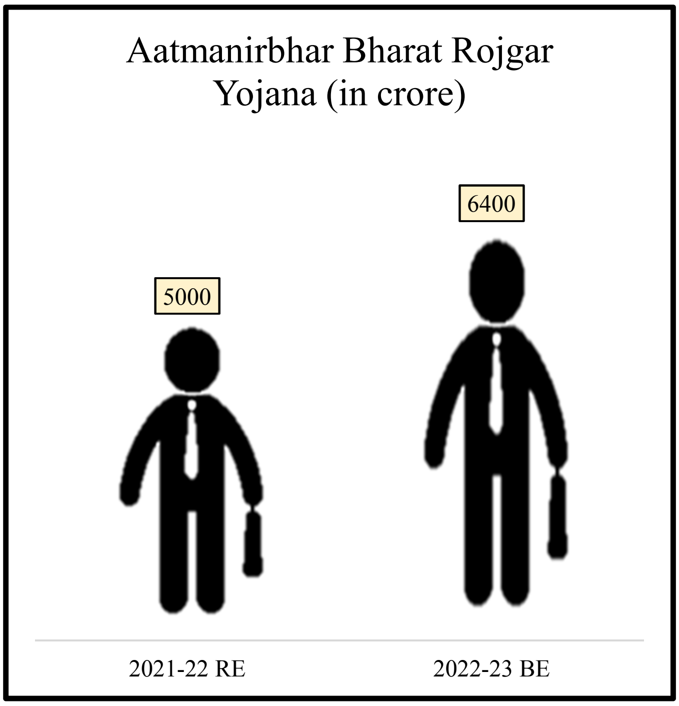

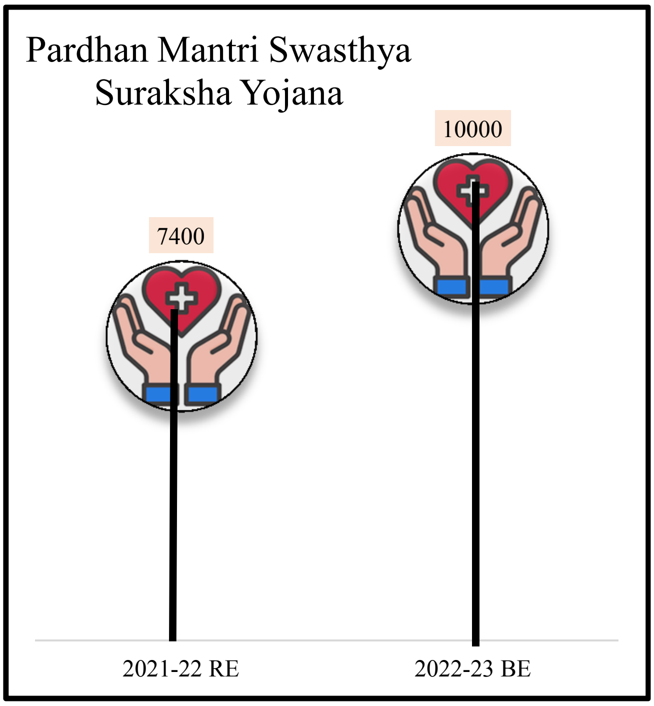

मंत्रालयवार आवंटन